come of Rs. one lakh during the course of the search and cash of Rs. 20,000 was seized from his residence.

(c) In view of reply to part (b) above, does not arise.

**Evasion of Income-tax by FPS owners in Delhi/New Delhi**

3519. DR. RATNAKAR PANDEY: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that most of the dealers of essential commodities, especially the FPS owners in Delhi and New Delhi, namely Shri Lakshmi Narain of Navrang Colony, Delhi and Shri Suraj Bhan of Tri Nagar, Delhi are avoiding the payment of a large sum towards income-tax with the collusion of Income Tax Officials;

(b) if so, what are the details of the raids conducted in the recent past against such dealers and how much unaccounted assets/jewellery have been recovered from them; and

(c) if no raid has been conducted, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF REVENUE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI AJIT PANJA): (a) It has been reported by the concerned Chief Commissioner of Income-tax that no case of tax evasion by FPS owners in Delhi and New Delhi namely Shri Lakshmi Narain of Navrang Colony, Delhi and Shri Suraj Bhan of Tri Nagar, Delhi has come to notice so far.

(b) No searches have been conducted in the cases of such dealers in the recent past.

(c) Income-tax searches are conducted only on the basis of the specific information regarding tax evasion available with the Income-tax authorities. In the absence of such information, no searches can be conducted.

**स्वीकृति के लिए लम्बित पड़ी राजस्थान की सिंचाई परियोजनाएं**

3520. **श्री सन्तोष बागड़ोदिया :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान की उन सिंचाई परियोजनाओं के नाम क्या है जो केन्द्रीय सरकार के पास स्वीकृति हेतु लंबित पड़ी है और परियोजनाश: ये कितने समय से लंबित पड़ी हैं ;

(ख) इन्हें स्वीकृति मिलने में हुये विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) इन परियोजनाओं को कब तक अनुमति मिल जाने की संभावना है?

**जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) :** (क) से (ग) पांच वृहद और दो मध्यम परियोजनायें नामश: गलवा आधुनिकोकरण, पिपलोआ लिफ्ट, सिद्धमुख, नोहर, माउंट आबू बहुउद्देशीय, गरारदा सिंचाई तथा सुवर्ली । एक वृहद परियोजना वर्ष 1983 में तथा दूसरी वर्ष 1986 में प्राप्त हुई थी, और शेष वर्ष 1988 में प्राप्त हुई थीं । पांच वृहद परियोजनाओं पर टिप्पणियां अनुपालना हेतु राज्य सरकार को भेज दी गयी थीं । दो वृहद परियोजनाओं की संशोधित रिपोर्ट हाल ही में प्राप्त हुई हैं ।

**राजस्थान में रुग्ण औद्योगिक एककों को पुन: शुरू करना**

3521. **श्री सन्तोष बागड़ोदिया :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा रुग्ण औद्योगिक कंपनियां (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 के अंतर्गत राजस्थान में पता लगाये गए रुग्ण औद्योगिक एककों का जिला-वार ब्यौरा क्या है ; और

(ख) इन एककों को पुन: शुरू करने के लिए क्या उपाय करने का विचार किया गया है ?

**वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री** (श्री एडुवर्डो फेलेरियो) : (क) औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने सूचित किया है कि रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबन्ध) अधिनियम 1985 के अंतर्गत रुग्ण कंपनियों का जिलेवार ब्यौरा संकलित नहीं किया जाता है। औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने सूचित किया है कि 31 दिसम्बर, 1988 की स्थिति के अनुसार रुग्ण, औद्योगिक कंपनी विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1985 की धारा 15 के अंतर्गत राजस्थान में फैक्टरी (फैक्टरियों) वाली औद्योगिक कंपनियों से संबंधित 30 मामले दर्ज किए गए थे।

(ख) रुग्ण औद्योगिक एककों को पुनरूज्जीवित करने के लिए अपेक्षित उपाय अधिनियम, की धारा 18(1) में दिये गये है।

**राजस्थान में ग्रामीण बैंकों की शाखाएं**

3522. **श्री सन्तोष बागड़ोदिया** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय राजस्थान में ग्रामीण बैंकों की कुल कितनी शाखायें काम कर रही हैं ;

(ख) क्या सरकार राज्य में इस प्रकार के बैंकों की नई शाखायें खोलने का विचार रखती है ; और

(ग) यदि हां, तो भीलवाड़ा जिले में इस प्रकार की कितनी शाखायें और किन-किन स्थानों पर खोलने का विचार है ?

**वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुवर्डो फेलेरियो)** : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि दिसम्बर, 1988 के अन्त में राजस्थान में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की 1034 शाखायें कार्य कर रही थी। वर्ष 1985–90 की वर्तमान शाखा लाइसेंसिंग नीति के अन्तर्गत, भारतीय रिजर्व बैंक ने राजस्थान में शाखायें खोलने के वास्ते क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 120 ग्रामीण तथा अर्ध-शहरी केन्द्र आवंटित किये हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने आगे बताया है कि भीलवाड़ा जिले में कम बैंक सुविधाओं वाला ऐसा कोई खंड नहीं है जहां वर्तमान शाखा लाइसेंसिंग नीति में निर्धारित मानदंडों को पूरा करने के लिये अतिरिक्त बैंक कार्यालय खोलने की आवश्यकता हो।

**रायपुर, मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना**

3523. **श्री अजीत जोगी** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री राज्य सभा में क्रमशः 10 नवम्बर, 1986 और 26 नवम्बर, 1987 को तारांकित प्रश्न 99 और तारांकित प्रश्न 297 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बतायेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जसवंत सिंह आयोग की सिफारिशों के अनुसार रायपुर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के खंडपीठ की स्थापना करने के प्रस्ताव के संबंध में मध्य प्रदेश सरकार की टिप्पणियां और विचार प्राप्त किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) रायपुर में उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना करने के संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जायेगा ?

**विधि और न्याय मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द)** : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

**Agitation by Bodos in Assam**

3524. SHRI CHITTA BASU:

SHRI DEBA PRASAD RAY:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Bodo Adivasis' agitation in Assam has taken a seri-